उत्पादन शुल्क तथा अन्य करों से मुक्त रखी गई आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएं

*165. **श्री आर० एल० पी० वर्मा :** क्या वित्त मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले बजट सत्र के दौरान जिन आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क और दूसरे करों की छूट दी गई थी उनकी बजट से पूर्व की कीमतें क्या थीं और छूट देने के पश्चात् अब उनकी कीमतें कितनी-कितनी निर्धारित की गई हैं ;

(ख) क्या ये उपभोक्ता वस्तुएं उपभोक्ताओं को सहज ही उपलब्ध हो जाती हैं; और

(ग) क्या किन्हीं कम्पनियों ने उत्पादन शुल्क में दी गई छूट का अनुचित लाभ उठाने की कोशिश की है और यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग). एक विवरण-पत्र सदन-पटल पर रखा गया है ।

विवरण-पत्र

(क) एक विवरण-पत्र संलग्न है ।

(ख) इस आशय की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है कि ये वस्तुएं लोगों को आसानी से नहीं मिल रही थीं ।

(ग) यद्यपि केन्द्रीय उत्पादनशुल्क कानून में ऐसी कोई विशेष व्यवस्था नहीं है कि निर्माता, उत्पादन शुल्क में कटौती के लाभ को अपने माल के खरीददार तक पहुंचाए, फिर भी विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालयों ने सम्बन्धित उद्योगों को कहा है कि शुल्क में हुई इन कटौतियों का लाभ उपभोक्ता तक पहुंचायें ।

विवरण-पत्र

मद	इकाई	बजट पूर्व मूल्य				थोक मूल्यों में बजट पश्चात् परिवर्तन			बजट पश्चात् मूल्य
		मूल मूल्य	उत्पादन शुल्क	विशेष उत्पादन शुल्क	जोड़	मूल मूल्य	उत्पादन शुल्क	विशेष उत्पादन शुल्क	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. सिलाई मशीनें									
(1) रीटा–आर0ए0—101 हस्त चालित फैमली मशीन कवर के बिना	प्रति नग	260.00	20.80 (8 प्रतिशत)	शून्य	280.80	288.00	शून्य	शून्य	288.00
(2) रीटा—आर0 ए0101 पाद-चालित फैमली मशीन–कवर के बिना	यथोपरि	436.00	34.88 (@8 प्रतिशत)	शून्य	470.88	500.00	शून्य	शून्य	500.00
II. साइकिल और साइकिल के पुर्जे—									
(1) एटलस साइकिल	यथोपरि	312.60	13.88 (5 प्रतिशत)	शून्य	326.48	312.60	शून्य	शून्य	312.60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(2) रैले 24"	यथोपरि	445.00	(इसमें उत्पादन शुल्क शामिल है)		445.00	440.00	शून्य	शून्य	440.00
(3) हरकुलिस जेंट्स पापुलर ब्लैक	यथोपरि	358.68	16.11 (5 प्रतिशत)	शून्य	374.79	369.00	शून्य	शून्य	369.00
III. वर्तित जल (मृदु पेय):									
(1) कैम्पा कोला	24 का डाला	11.05	6.63	—	17.68	12.00	4.80	0.24	17.04
(2) गोल्ड स्पॉट	यथोपरि	14.81	4.44	—	19.25	12.62	5.05	0.25	17.92
(3) सोडा स्पेशल	यथोपरि	4.55	0.91 (20 प्रतिशत)	—	5.46	4.00	0.80	0.04	4.84
IV. दूध पेस्ट :									
(1) फारहेन्स 150 ग्राम	दर्जन	71.00	14.20	—	85.20	71.02	7.10	0.36	78.48
(2) बिनाकाफ्लोराइड 40 ग्राम	प्रति नग	1.86	0.37	—	2.23	1.86	0.19	0.01	2.06
V. साबुन :									
सरल साबुन (100 ग्राम)	144 (टिक्कियां)	106.32	—	—	106.32	101.73	—	—	101.73
VI. विद्युत् बल्ब :									
(1) बजाज 25 वाट बी0 सी0 क्लियर	प्रति नग	2.71	—	—	2.71	2.71	—	—	2.71
(2) फिलिप्स जी0 एल0 एस0. 40 वाट गैस भरी कायल	यथोपरि	3.06	—	—	3.06	3.06	—	—	3.06

@ मूल्यों में उत्पादन शुल्क शामिल है ।

	फुटकर मूल्य		
	बजट पूर्व मूल्य	बजट पश्चात् मूल्य	
VI. प्राण रक्षक औषधि-द्रव्य :			
(1) टेट्रासाइक्लीन कैप्सूल (प्रति 100) . . .	48.50	48.50	(10–9–80)
(2) आयडोक्लोर हाइड्रोक्सीक्वीनोलीन (प्रति 1000) . . .	95.00	95.00	(10–9–80)
VII. प्रेशर कुकर :			
"प्रिस" 5 लिटर (आधानों के बिना)	167.20	160.60	(17–11–80)
"प्रिस" 3 लिटर (आधानों के बिना)	147.40	140.80	"
"हाकिन्स" 4 लिटर	184.00	176.85	"
5 लिटर	197.50	189.55	"

टिप्पणी :—उपर्युक्त मदों में से प्रत्येक के अन्तर्गत उत्पादों की अनेक किस्में हैं और इनकी कोई व्यापक सूची प्रस्तुत कर पाना व्यवहारिक नहीं है । इस सूची में, प्रत्येक मद के अन्तर्गत दो या तीन चुनिन्दा किस्मों के उत्पादों के सम्बन्ध में ही सूचना दी गई है ।

PARLIAMENT LIBRARY
No. 97362(3)

श्री रोतलाल प्रसाद वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। विगत बजट सत्र में मंत्री जी ने बड़े ही पुरजोर शब्दों में इस सदन को आश्वासन दिया था और घोषणा की थी जिस पर सदस्यों ने मेजें थपथपाई थीं कि जनता की आवश्यक वस्तुओं के मूल्य गिराये जायेंगे और उन्होंने कई चीजों पर उत्पादन कर घटाया था। पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन चीजों का उत्पादन-कर उन्होंने घटाया था उन सारी चीजों के दाम आज बाजार में और भी ज्यादा हैं। केवल एक दो चीजें नमूने के रूप में, जो उन्होंने आश्वासन दिया था, उसके बावजूद जो दाम बढ़े हैं बताता हूं। बाकी चीजों में सरकार के आदेश का पूरा पूरा उल्लंघन हुआ है।

सिलाई मशीन के लिए सरकार ने घोषणा की थी कि गृहणियों के लिए उसके दाम घटाये गये हैं तो बजट के पहले उसके दाम 260 रुपये थे और अब 288 रुपये हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसमें कहां फायदा हुआ है? उत्पादन कर घटाने के बावजूद भी दाम 260 के बजाय 288 रुपये हो गये हैं। उसी तरह से बल्ब के लिए भी देखें तो उसकी भी वही हालत है, उसके दाम भी नहीं घटे हैं। साइकिल और सौफ्ट ड्रिंक्स का जहां तक सवाल है ...

MR. DEPUTY SPEAKER: What is your question? What do you want to know from the Government?

श्री रोतलाल प्रसाद वर्मा : मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण कर रहा हूं। क्वैश्चन इसी तरह से आपके सामने बनेगा।

मंत्री जी ने कहा है कि डीजल इंजन का दाम घटायेंगे जिससे जो पैट्रोल से टैक्सी चला रहे हैं, वह डीजल से चला सकेंगे, लेकिन उसका भी कोई दाम नहीं घटा है। अगर घटा है तो मंत्री जी बतायें कि कितना घटा है? दियासलाई भी 20 पैसे की बिक रही है। मंत्री जी बतायें कि उन्होंने जो छूट दी है, बजट के पहले जो भाव थे, उसमें कितनी गिरावट आई है या नहीं आई है?

अगर हुआ है तो उसको देखने के लिए क्या आप के इंस्पैक्टर बाजारों का भ्रमण करते हैं और देखते हैं कि दाम गिरे हैं या नहीं और आम जनता को ये वस्तुएं गिरे हुए दामों पर उपलब्ध हो रही हैं या नहीं?

MR. DEPUTY SPEAKER: The Minister will reply.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI R. VENKATARAMAN): Sir, prices of all commodities are not controlled and where prices are not controlled Government cannot issue any order saying that prices should be fixed at a particular level or at a particular thing. In the Budget statement I said, 'I hope the trade will play fair in passing on the concessions which I am making, to the consumers.' I did not say that the prices will be reduced as a result of the excise concessions which I had given.

The second part of the Question: the hon. Member is misleading the statement. He is unable to read the statement properly. Now, I will show. He said that in respect of aerated water it was eleven rupees for a case of 24 and it has become Rs. 17. He did not understand that Rs. 11.05 was the basic price, the excise duty was Rs. 6.63 paise and the total selling price at that time was Rs. 17.68 paise. After the Budget, the price was Rs. 12, the excise duty was Rs. 4.80 paise, special excise duty 24 paise, and the selling price was Rs. 17.04 paise. Though I do not take credit for this small reduction, I want to point out that he is mis-reading the figures. He is unable to read the figures. This applies to all the figures which he has quoted. The effort which the Government has made is to prevent a further increase in

prices by cutting down excise duties. There are number of factors which go to increase the prices. The in-put costs in respect of drugs has gone up and there has been a Committee Constituted to review the price of essential drugs. As a result of the Committee's recommendation prices went up. It was not because that the excise duty was increased the price of essential durgs had increased. Whenever you have a price rise of a particular article, you must take into account what are the factors which led to the increase in price. My submission to the House is, if the concessions had not been given, the prices would have gone further up because when we have higher excise, duty, the higher duty would have added to the price and the cost would have been higher. (*Interruptions*).

SHRI R. L. P. VERMA: I have not yet completed the supplementary.

MR. DEPUTY SPEAKER: That is another supplementary.

श्री रोतलाल प्रसाद वर्मा : मंत्री महोदय ने कहा कि मैंने जो कहा है वह मिसलीडिंग है । लेकिन आप देखें कि जो साफ्ट ड्रिंक एक रुपये में मिलता था उसको 75 पैसे में बाजार में बिकना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ है ।

मेरा सवाल होने के बाद प्रेशर कुकर्ज के दाम गिरे हैं, 17-11-80 से गिरे हैं । इसके पहले ज्यादा दाम थे । पहले जो ज्यादा दाम थे और उनको लेकर जिन्होंने एक्साइज ड्यूटी की छूट का अनुचित लाभ उठाया है उनके खिलाफ क्या सरकार कोई कानूनी कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

SHRI R. VENKATARAMAN: Sir, I only pointed out the mistake, the erroneous way in which he was reading the statistics. I am free to confess that the reduction in the wholesale price has not been translated in the retail prices. The retail prices have not fallen in sympathy with the wholesale price. There is a time lag between the reduction in the wholesale price and the retail price. As I mentioned, Government have no power to control all the prices and it will be difficult for Government to fix prices and say that a commodity must be sold at a particular price. What we expect is by the operation of law of supply and demand, by further increased production and concessional duties the price will be kept at a controlled lower level.

श्री रामावतार शास्त्री : उपाध्यक्ष जी, मंत्री जी ने जो वक्तव्य और आंकड़े पेश किये हैं उनमें टूथपेस्ट और साबुन का भी जिक्र है । इन दोनों चीजों को मध्यम वर्ग के लोग और गरीब लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि उत्पादन शुल्क में या दूसरे करों में छूट देने के बावजूद पिछले बजट अधिवेशन के बाद साबुन और टूथपेस्ट की कीमतों में बढ़ोत्तरी हुई है ? अगर हुई है तो उसको रोकने के लिए सरकार ने कौन सी कार्यवाही की और इसमें कमी करने के लिए कोई विचार या योजना वगैरह सरकार के दिल में है या नहीं ?

MR. DEPUTY-SPEAKER: One 'Rama' is putting question to another 'Rama'.

SHRI R. VENKATARAMAN: With regard to tooth pastes, the following are the reported rates in the Super Bazar, Connaught Circus, New Delhi:

Signal tooth paste—200 grams—pre-Budget price—Rs. 10.55, Post Budget—Rs. 9.40.

Binaca tooth paste 200 grams pre-budget price—Rs. 10.35, post Budget—Rs. 9.65.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: What is the retail price?

SHRI R. VENKATARAMAN: These are the retail rates in the Super Market. We must go by certain yardstick. If the hon. Member says that a higher price is prevailing in some odd place, I have no means of checking that. We should follow certain standards.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: I have told you about Super Bazar. Let the hon. Minister accompany me to the Super Bazar here in Parrliament House.

MR. DEPUTY-SPEAKER It seems that Mr. Ramavatar Shastri's Super Bazar is different from the Super Bazar of Mr. Venkataraman.

SHRI R. VENKATARAMAN: I am willing to go with the hon. Member anywhere but I am not willing to go with him in the market.

Actually, my esteemed colleague, Dr. Chanana, had called the meeting of some of the industrialists, had a discussion with them and pointed out to them that these were the concessions that had been given and it was upto the trade to behave itself. It is as a result of that that some reductions have been made. It is not right to say that there is no reduction. The position is that in respect of certain items, there is no reduction. For the purpose of satisfying Government, they reduce in crtain other items. But the fundamental thing is that as long as Government do not have the power to control the price, you cannot hold me responsible for that. All that we can do is to exercise our general influence, give them the facility and the concessions.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: In view of the rising prices and in view of the fact that he expected fairplay and there is foul play by the traders and producers, is he going to concede the demand that essential commodities of mass production, particularly consumed by the poor, should be subsidised by the Central Government and, if any State Government wants to do it, is the Central Government going to come forward and help the State Government and make available to them the necssary commodities and give financial assistance?

SHRI R. VENKATARAMAN: This is a budget matter. I cannot disclose it at this stage.

श्रीमती प्रमिला दंडवते : उपाध्यक्ष महोदय, इस लिस्ट में सरल सोप के बारे में बताया गया है कि एक्साइज ड्यूटी पहले भी नहीं थी और आज भी नहीं है, लेकिन पहले 144 टिक्कियों की कीमत 106 रु० थी और अब वह 101 रु० 73 पै० हो गई है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि यह जनता का जो सरल साबुन है, उसका प्रोडक्शन हमारे देश में कितना है और दूसरी जितनी टिक्कियां हैं, उनका कितना परसेंटेज है ? जहां तक मुझे पता है, इस प्रकार का साबुन हमारे देश में ज्यादातर अवेलेबल ही नहीं है—इस तरह की फिगर्स दे कर तो गुमराह करना है।

SHRI R. VENKATARAMAN: I do not know what is the percentage of production for Saral soap in relation to the total soap. All that I can say is tht we have taken certain representative samples and have given them in the list. Some of them show there has been reduction, some of them show there has been no reduction and some of them show there is increase. I have not said that in every one of these cases there has been a reduction.

The second point which the hon. lady Member made was that it is not available in the market. The availability is dependent on the supply and demand position. Certain commodities at certain times do not become available, because of short supply. So long as the Government does not control the entire production, it cannot be held responsible for non-availability of certain things of that kind. Certainly, Government should be held responsible for non-availability of essential commodities like food.

The hon. lady Member said that I was misleading or leading somebody in the garden path. Certainly, I would like to lead somebody in the garden path. Let us have some garden and let us walk together. Then we may have some better idea of the world.

श्री धर्म दास शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय [मंत्री जी] से विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि हम सब लोगों ने माननीय मंत्री जी की बजट पर भूरी-भूरी प्रशंसा की थी, लेकिन हमने जो करों में छूट दी है, क्या इस बारे में सरकार सोच रही है कि जीवनोपयोगी वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण किया जाएगा और क्या सरकार

इस बारे में कदम उठाने वाली है ? इस बारे में हमको अवगत कराने का कष्ट करें

SHRI R. VENKATARAMAN: The question of control of essential commodities is always engaging the attention of the Government. If at any time any of the essential commodities go up in prices beyond the reach of the common man, there are various ways in which it can be tackled. One is the distribution of the commodity at a fair price through the public distribution system so as to make it available at reasonable price. It is not necssarily by control of prices that we ensure that the commodities are available at reasonable prices. In fact, it has been our sad experience that mere control without proper distribution arrangements fails. We will take all these factors into account and see to it that the essential commodities are made available at reasonable prices.

Construction of Air Terminal Building at Leh

*166. SHRI P. NAMGYAL: Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the construction of air terminal building at Leh airport has been held up due to non-availability of funds;

(b) whether it is also a fact that air passengers on the Srinagar-Leh route are facing great hardships due to lack of accommodation and other facilities at the Leh airfield; and

(c) if replies to parts (a) and (b) above be in the affirmative, what steps Government propose to take to expedite the construction of new air terminal building and to renovate the existing temporary shelter till the new building is completed?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI CHANDULAL CHANDRAKAR): (a) to (c). Passenger handling facilities at Leh aerodrome are provided in renovate Nissan huts. A permanent terminal building is under construction through the agency of Jammu and Kashmir Public Works Department at an estimated cost of Rs. 14.95 lakhs. Funds for tthe new terminal building are provided in the plan. Payment of Rs. 5 lakhs had already been made to the Jammu and Kashmir Public Works Department. Balance payment will be made to the Jammu and Kashmir Public Works Department after they have completed the necessary formalities.

SHRI P. NAMGYAL: Mr. Deputy-Speaker, Sir, as stated by the hon. Minister, Rs. 5 lakhs has been released, but until very recently this amount has not been received. If it is released, I would like to know when this amount has been released. And then, the J&K PWD is supposed to complete some formalities for the release of the remaining amount. I would like to know which are those formalities.

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI A. P. SHARMA): There is no question of not releasing this amount of Rs. 5 lakhs to the Jammu and Kashmir Government. They have accepted that position. What is required is that we have asked them as to how they have spent that money and on that question recently they have submitted some statement to the Government and the Government is considering the payment of the balance to the Jammu and Kashmir Government for completion of the work.

The hon. Member wanted to know the time. It was released in December, 1979.

SHRI P. NAMGYAL: Sir, as you know, Ladakh is a land-locked country and remains cut off from the rest of the country for over six months in a year and every article for building material is to be lifted from the Kashmir valley and that is to be done before the closure of the road. Because of the shortage of funds, the concerned departments have not been able to stock enough materials like cement; steel and timber etc. I would like to have an assurance from the hon. Minister as to whether the hon. Minis-